

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून दिनांक 22 जनवरी, 2016

विषय: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालकुंआ, जनपद नैनीताल के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7प/1/69/2013/21804, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालकुंआ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत ₹ 362.91 लाख के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि ₹ 332.44 लाख (₹301.37 लाख सिविल कार्यों हेतु एवं 31.07 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु) की धनराशि की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष वर्तमान में ₹ 50.06 लाख (पचास लाख छः हजार मात्र) की धनराशि संलग्न साफ्टवेयर आवंटन आई0डी0सं-S1601120252, दि0 21.01.2016 माध्यम से अवमुक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधनित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

8. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य के सम्बन्ध वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार कार्यवाही संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. भविष्य में प्रश्नगत योजना के पुनरीक्षित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 103-अस्पताल तथा औषधालय, 03-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना), 00-आयोजनागत, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा सं0-333(P)XXVII(3)/2015-16 दिनांक 21 जनवरी 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या- 89 (1)/XXVIII-5-2016-06(घो0)/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल।
- 5- परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 6- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
- 8- मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव